



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 160]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 15, 2007/ज्येष्ठ 25, 1929

No. 160]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 15, 2007/JYAISTHA 25, 1929

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 15 जून, 2007

सं. 11-7/2004-बागवानी-IV.—कृषि में प्लास्टिक के प्रयोग संबंधी राष्ट्रीय समिति (एन.सी.पी.ए.) का मूल रूप से रसायन एवं पैट्रो रसायन विभाग में 1981 में गठन किया गया था, जिसने 1993 से कृषि एवं सहकारिता विभाग में कार्य करना शुरू कर दिया। 1996 में इसका पुनर्गठन किया गया था। इस समिति को अधिक प्रभावी बनाने के लिए और बागवानी में प्लास्टिक के अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए समन्वित रीति से इसके कार्यों का केन्द्रण करने के लिए एन.सी.पी.ए. का बागवानी में राष्ट्रीय प्लास्टिक अनुप्रयोग समिति (एन.सी.पी.ए.एच.) के रूप में 2001 में पुनर्गठन किया गया था। तत्पश्चात् एन.सी.पी.ए.एच. का दिनांक 17-6-2004 को 3 वर्ष की अवधि के लिए पिछली बार पुनर्गठन किया गया था। यह निर्णय लिया गया है कि कृषि एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत बागवानी में राष्ट्रीय प्लास्टिकलचर अनुप्रयोग समिति (एन.सी.पी.ए.एच.) (एतश्मिन समिति के रूप में संदर्भित) का पुनर्गठन किया जाए। समिति का गठन एवं विचारार्थ विषय निम्न प्रकार से हैं : —

क. गठन

- |                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| 1. केन्द्रीय कृषि मंत्री              | अध्यक्ष   |
| 2. कृषि राज्य मंत्री                  | उपाध्यक्ष |
| 3. सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग      | सदस्य     |
| 4. सचिव, रसायन एवं पैट्रो रसायन विभाग | तदैव      |

- |  |       |
|--|-------|
| 5. सचिव (डेयर) एवं महानिदेशक (भा.कृ.अनु. परि.) | सदस्य |
| 6. सचिव, जल संसाधन मंत्रालय                    | तदैव  |
| 7. सचिव, पंचायती राज मंत्रालय                  | तदैव  |
| 8. अपर सचिव, बागवानी का आई/सी.कृ. एवं सह.      | तदैव  |
| 9. कृषि आयुक्त, कृ. एवं सह.                    | तदैव  |
| 10. उप महानिदेशक (बागवानी) भा.कृ.अनु.परि.      | तदैव  |
| 11. वित्तीय सलाहकार (कृ.एवं सह. वि.)           | तदैव  |
| 12. प्रमुख सलाहकार (कृषि), योजना आयोग          | तदैव  |
| 13. संयुक्त सचिव (एन.एच.एम.), कृ. एवं सह.      | तदैव  |

चार राज्य सरकारों के प्रतिनिधि

- |   |       |
|---|-------|
| 14. कृषि उत्पादन आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश सरकार      | सदस्य |
| 15. प्रमुख सचिव (कृषि/बागवानी), महाराष्ट्र सरकार  | तदैव  |
| 16. सचिव (बागवानी), उत्तर प्रदेश सरकार            | तदैव  |
| 17. प्रमुख सचिव (बागवानी), जम्मू एवं कश्मीर सरकार | तदैव  |

नाबार्ड के प्रतिनिधि

- |  |       |
|--|-------|
| 18. मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, मुम्बई | सदस्य |
|--|-------|

**भारतीय मानक ब्यूरो के प्रतिनिधि**

19. निदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली सदस्य

**दो राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के उपकुलपति**

20. उपकुलपति, इन्दिरा गांधी विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ सदस्य

21. उपकुलपति, महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ, राहुरी तदैव

**हाई-टैक बागवानी उद्योग के प्रतिनिधि**

22. अध्यक्ष, भारतीय सिंचाई संघ, बंगलौर सदस्य

23. ग्रीन हाउस विनिमाताओं के प्रतिनिधि तदैव

24. माइक्रो प्रोपोगेशन (टीसी) इकाइयों के प्रतिनिधि तदैव

**किसान संघ**

25. अध्यक्ष, भारतीय बागवानी संघ, पुणे सदस्य

**सदस्य सचिव**

26. बागवानी आयुक्त सदस्य सचिव

**ख. विचारार्थ विषय**

- (i) प्लास्टिकलचर अनुप्रयोग के माध्यम से बागवानी विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष संदर्भ में उपलब्ध जल संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने के लिए और उत्पाद की गुणवत्ता सुधारने के लिए योजनाएं तैयार करना।
- (ii) कृषि में प्लास्टिक के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सब्सिडी सहायता देने, वित्तीय नीति जैसे उपयुक्त नीति उपायों की सिफारिश करना।
- (iii) ड्रिप सिंचाई पद्धतियों, ग्रीन हाउसों, मल्लिंग पैकेजिक इत्यादि जैसे विभिन्न प्लास्टिकलचर अनुप्रयोगों के वृद्धि अधिग्रहण एवं प्रचार के लिए नीतियों के सुझाव देना।
- (iv) अनुसंधान एवं विकास के संवर्धन को व्यवस्थित करना, डाटा बेस का निर्माण करना, कृषि में प्रयुक्त प्लास्टिक के लिए गुणवत्ता मानक निर्धारण करने में सहायता करना जल प्रबंधन इत्यादि।
- (v) केंद्रीय प्रायोजित लघु सिंचाई स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश उपलब्ध कराना।
- (vi) देश में सामान्य तौर पर प्लास्टिकलचर के समग्र विकास के लिए विशेष तौर पर प्रीसिजन कृषि विकास केंद्रों के प्रभावी रूप से निष्पादन का प्रबोधन करना और निरीक्षण करना।
- (vii) देश में प्लास्टिकलचर के संवर्धन से जुड़ा कोई अन्य मामला।

2. एनसीपीएच की अवधि संकल्प के जारी होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी। अध्यक्ष, एनसीपीएच की सहमति से गैर-सरकारी सदस्य पद ग्रहण करेंगे। समिति की बैठक जब कभी आवश्यक होगी तभी आयोजित की जायेगी लेकिन वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होगी। समिति सरकार को वार्षिक आधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

3. समिति के लिए अपेक्षित लिपिकीय सहायता जारी रहेगी जिसे भारतीय पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, दिल्ली में अवस्थित किसी अन्य उपयुक्त एजेंसी से आउटसोर्सिंग से लिए गए कर्मिकों द्वारा सेवा के लिए एनसीपीएच के केंद्रीय समन्वय कक्ष द्वारा उपलब्ध कराया जाना है।

4. समिति के कार्य व्यापार संबंधी व यात्राओं के संबंध में राज्य कृषि विश्वविद्यालय के कुलपतियों और गैर-सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते संबंधी व्यय को समिति के लिए आर्बिट्ररी राशियों में से पूरा किया जायेगा। अन्य पदेन सदस्यों के संबंध में चालू व्यय उनके संबंधित विभागों द्वारा वहन किया जायेगा।

डॉ. एम. एल. चौधरी, बागवानी आयुक्त

**MINISTRY OF AGRICULTURE**

(Department of Agriculture and Cooperation)

**RESOLUTION**

New Delhi, the 15th June, 2007

No. 11-7/2004-Hort. IV.—The National Committee on use of Plastics in Agriculture (NCPA) which was originally constituted in the Department of Chemicals and Petrochemicals in 1981 has been functioning in the Department of Agriculture and Cooperation since 1993. It was reconstituted in 1996. In order to make this Committee more effective and to focus its endeavour in a coordinated manner for promoting the applications of plastics in Horticulture, NCPA was reconstituted in 2001 as National Committee on Plasticulture Applications in Horticulture (NCPAH). Thereafter, NCPAH was last reconstituted on 17-6-2004 for a period of 3 years. It has been decided to reconstitute National Committee on Plasticulture Applications in Horticulture (NCPAH) (hereinafter referred to as the Committee) under the Department of Agriculture and Cooperation. The composition and Terms of Reference (TOR) of the Committee are as under :—

**A. Composition:**

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Union Agriculture Minister                        | Chairman      |
| 2. Minister of State for Agriculture                 | Vice-Chairman |
| 3. Secretary, DAC                                    | Member        |
| 4. Secretary, Deptt. of Chemicals and Petrochemicals | -do-          |
| 5. Secretary (DARE) & DG(ICAR)                       | -do-          |
| 6. Secretary, Ministry of Water Resources            | -do-          |

7. Secretary, M/o Panchayati Raj	Member
8. Addl. Secretary I/c of Horticulture, DAC	-do-
9. Agriculture Commissioner, DAC	-do-
10. Dy. Director General (Hort.), ICAR	-do-
11. Financial Adviser, DAC	-do-
12. Principal Adviser (Agri.), Planning Commission	-do-
13. Joint Secretary (NHM), DAC	-do-
<b>Representative of four State Governments</b>	
14. Agriculture Production Commissioner, Govt. of Andhra Pradesh	Member
15. Principal Secretary (Agri/Hort.), Govt. of Maharashtra	-do-
16. Secretary (Horticulture), Government of Uttar Pradesh	-do-
17. Pr. Secretary (Horticulture), Government of J&K	-do-
<b>Representative of NABARD</b>	
18. Chief General Manager, NABARD, Mumbai	Member
<b>Representative of Bureau of Indian Standards</b>	
19. Director, BIS, New Delhi	Member
<b>Vice Chancellors of two State Agricultural Universities</b>	
20. Vice Chancellor, Indira Gandhi Agriculture University, Raipur, Chattisgarh	Member
21. Vice Chancellor, Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth, Rahuri	-do-
<b>Representatives of Hi-tech Horticulture Industry</b>	
22. President, Irrigation Association of India, Bangalore	Member
23. Representative of Green House Manufacturers	-do-
24. Representative of Micropropagation (TC) Units	-do-
<b>Farmer's Associations</b>	
25. President, Confederation of Indian Horticulture, Pune	Member
<b>Member Secretary</b>	
26. Horticulture Commissioner	Member Secretary

**B. Terms of Reference**

- (i) To prepare plans for promoting horticulture development through plasticulture applications with special reference to optimizing the use of available water resources and improving quality of the product.
- (ii) To recommend suitable policy measures such as a fiscal policy, subsidy assistance to farmers etc. for promotion of use of plastics in agriculture.
- (iii) To suggest strategies for propagation and increased adoption of various plasticulture applications like drip irrigation systems, green houses, mulching packaging etc.
- (iv) To arrange promotion of Research and Development, to build data-base, to assist in prescribing quality standards for plastics used in agriculture, water management, etc.
- (v) To provide guidelines for effective implementation of centrally sponsored scheme of micro-irrigation.
- (vi) To supervise and monitor effectively the performance of Precision Farming Development Centres (PFDCs) in particular and overall development of plasticulture in general in the country.
- (vii) Any other matter connected with promotion of plasticulture in the country.

2. The term of NCPAH will be for a period of three years from the date of issue of the Resolution. The non-official members shall hold office with the pleasure of the Chairman, NCPAH. The committee shall meet as often as necessary but at least once in a year. The Committee shall submit its report to the Government on annual basis.

3. The Secretarial assistance required for the Committee will continue to be provided by the Central Coordination Cell of NCPAH serviced by personnel drawn from the Indian Petrochemicals Ltd./outsourcing from any other suitable agency located at Delhi.

4. The expenditure on TA/DA of the Vice-Chancellors of State Agricultural Universities and the non-official members in connection with the journeys undertaken on Committee's business will be met out of the funds allocated for the Committee. The corresponding expenditure in respect of other ex-officio members will be borne by their respective Departments.

Dr. M. L. CHOUDHARY, Horticulture Commissioner